



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052024-254082
CG-DL-E-07052024-254082

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1846]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 2024/वैशाख 17, 1946

No. 1846]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 2024/VAISAKHA 17, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2024

का.आ. 1939(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के पहली अनुसूची के मद 6 के अधीन आच्छादित ऐसे उद्योग की सेवाएँ, जो खाद्य सामग्री में लगे हुए हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी ;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4869(अ), तारीख 9 नवंबर, 2023 द्वारा, तारीख 9 नवंबर, 2023 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में और छह महीने के लिए उक्त उद्योग को लोकउपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उप-खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, जो इस प्रकार है:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लोक उपयोगिता सेवाएं (चौथा आदेश) 2024 है।
- यह 9 मई, 2024 से प्रवृत्त होगा।

2. केंद्रीय सरकार, खाद्य सामग्री में लगी हुई सेवाओं को 9 मई, 2024 से छह मास की और अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/07/2024-आई.आर.(पी.एल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2024

S.O. 1939(E).— Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industry engaged in Food stuffs, which is covered under item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 9th November, 2023 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4869(E), dated the 9th November, 2023;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby issues the following order as follows: -

1. Short title and Commencement. - (1) This order may be called the Public Utility Services (Fourth Order) 2024.

(2) It shall come into force on the 9th day of May, 2024.

2. The Central Government hereby declares the services engaged in Food stuffs to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from 9th May, 2024.

[F. No. S-11017/07/2024-IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.